

जापान के सागा प्रांत के गवर्नर के शिष्टमंडल की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे से की मुलाखत

पर्यावरण, प्लास्टिक-मुक्ति, शिक्षा और दुग्ध व्यवसाय पर विस्तृत चर्चा



जमीर काज़ी मुंबई,: जापान के सागा प्रांत के गवर्नर के नेतृत्व में आए उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने शनिवार को पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे से आज मुलाखत की! इस अवसर पर पर्यावरण, प्लास्टिक-मुक्ति, शिक्षा सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। नदी पुनर्जीवन और प्लास्टिक-मुक्त जलस्रोत राज्य की प्राथमिकता हैं और इसके लिए जापान का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ऐसा विश्वास पर्यावरण मंत्री मुंडे ने व्यक्त किया।

मुंडे के 'रामटेक' स्थित शासकीय निवास पर आयोजित बैठक में समुद्र और नदियों में होने वाले प्रदूषण को रोकने, प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध संयुक्त प्रयास करने, तथा शिक्षा, पशुसंवर्धन और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर महाराष्ट्र और जापान के शिष्टमंडलों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई। जापान के सागा प्रांत के शिष्टमंडल का नेतृत्व गवर्नर योशिनोरी यामागुची ने

किया। उनके साथ क्षेत्रीय विनियम विभाग के उप-महानिदेशक मसाहिरो ओनो, अंतरराष्ट्रीय नीति समूह के उप-निदेशक कोजी योशिताके, परियोजना प्रमुख कोकी कनामारु तथा जेट्रो सागा के मुख्य निदेशक हिरोशी योनेयामा उपस्थित थे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय एवं मत्स्य व्यवसाय विभाग के सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव जयश्री भोज,

तथा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव देवेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर गवर्नर यामागुची ने जापान के तकनीकी ज्ञान, प्रबंधन अनुभव और अनुसंधान क्षमताओं को महाराष्ट्र के साथ साझा करने की तत्परता व्यक्त की। एशियाई समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए ज्ञान भागीदारी के माध्यम से संयुक्त पहल करने पर दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई।

दुग्ध व्यवसाय पर भी चर्चा

बैठक में शिक्षा क्षेत्र में सहयोग को भी विशेष महत्व दिया गया। पर्यावरणीय स्थिरता, पशु विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों को राज्य में अवसर उपलब्ध कराने की तैयारी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने व्यक्त की।

दुग्ध व्यवसाय और पशुसंवर्धन क्षेत्र में नवाचारों के साथ-साथ सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में जापान की उन्नत तकनीक महाराष्ट्र के लिए उपयोगी हो सकती है, ऐसा शिष्टमंडल ने कहा। इन क्षेत्रों में औद्योगिक और शैक्षणिक सहयोग बढ़ाने की पारस्परिक इच्छा भी व्यक्त की गई।

पर्यावरण मंत्री को जापान का निमंत्रण

प्लास्टिक प्रबंधन के लिए स्थापित किए जा रहे वर्ल्ड ओशन प्लास्टिक प्लानिंग सेंटर का दौरा करने का निमंत्रण गवर्नर यामागुची ने पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे को दिया। भविष्य में पारस्परिक दौरे, तकनीकी कार्यशालाएं और दीर्घकालिक सहयोग का रोडमैप तैयार करने पर भी चर्चा हुई।

राजुरी क्षेत्र के ८ से १० गांवों की सिंचाई समस्या विधायक संदीप क्षीरसागर के प्रयासों से हल

वंजारवाड़ी तालाब व नहर मरम्मत कार्य के लिए १ करोड़ ७ लाख रुपये की मंजूरी



बीड । प्रतिनिधि । दि. ७ जलसंपदा विभाग द्वारा वंजारवाड़ी लघु परियोजना तालाब तथा नहर (पाट) मरम्मत कार्य के लिए १ करोड़ ७ लाख रुपये की निधि के साथ मंजूरी प्रदान की गई है। यह कार्य वर्तमान में निविदा स्तर पर है और शीघ्र ही प्रत्यक्ष रूप से काम शुरू होने की संभावना है। इस परियोजना के पूरा होने से राजुरी परिसर के ८ से १० गांवों की कृषि सिंचाई की समस्या स्थायी रूप से हल हो जाएगी। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि विधायक संदीप क्षीरसागर के सतत

प्रयासों से संभव हो पाई है। बीड तालुका स्थित वंजारवाड़ी लघु परियोजना का तालाब वर्ष १९६५ में पूर्ण हुआ था। इस परियोजना की सिंचाई क्षमता १०५२ हेक्टेयर है। यह तालाब राजुरी क्षेत्र के ८ से १० गांवों के लिए कृषि सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत बन सकता है। हालांकि, लंबे समय पहले निर्मित होने के कारण मुख्य संरचना कमजोर हो गई थी, जिससे पानी का रिसाव होने लगा था और स्पिलवे की विभाजक दीवार भी जर्जर अवस्था में थी। ऐसे में आवश्यक

मरम्मत कार्य अत्यंत जरूरी हो गए थे। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए राजुरी क्षेत्र के किसान भाइयों ने आदर्श गांव वंजारवाड़ी के सरपंच वैजनाथ तांदळे के माध्यम से यह मुद्दा विधायक संदीप क्षीरसागर के समक्ष रखा। इसके बाद विधायक क्षीरसागर ने शासन और प्रशासन स्तर पर लगातार प्रयास किए। परिणामस्वरूप वंजारवाड़ी तालाब और नहर मरम्मत कार्य के लिए १ करोड़ ७ लाख रुपये की पर्याप्त निधि के साथ मंजूरी मिल गई। ▶▶पान ४ पे



विधायक विजय सिंह पंडित ने नगर पालिका के चीफ आफीसर फड, नगर अध्यक्ष पारवे ताई व सदस्यों के साथ मिलकर बीड शहर कि समस्या व उसके समाधान कि चर्चा कि ।

मुंबई की महापौर मराठी ही होंगी!

भाजपा की ऋतु तावड़े का चयन तय, उपमहापौर पद पर संजय घाड़ी

मुंबई । जमीर काज़ी एशिया की सबसे समृद्ध नगर पालिका मानी जाने वाली बृहन्मुंबई महानगरपालिका में मराठी महापौर बनाने का वादा भाजपा ने निभाया है। इसके तहत वरिष्ठ नगरसेविका ऋतु तावड़े ने शनिवार को महापौर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं उपमहापौर पद के लिए शिवसेना (शिंदे गुट) के



इस बीच, प्रमुख विपक्षी दल

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) द्वारा उम्मीदवार न उतारने की घोषणा के बाद ऋतु तावड़े का चयन लगभग तय माना जा रहा है। ११ फरवरी को इस पर औपचारिक मुहर लगने की संभावना है। मराठी अस्मिता के मुद्दे पर लड़ी गई इस चुनावी प्रक्रिया में महायुति ने कुल ११८ सीटें जीती हैं। प्रचार के दौरान भाजपा ने यह घोषणा की ▶▶पान ४ पे

अनिल अंबानी और कुख्यात जेफरी एपस्टीन के चौंकाने वाले चैट लीक, स्वीडिश लड़की की 'ऑफर' पर प्रतिक्रिया का दावा

मुंबई । जमीर काज़ी देश के कर्ज़दार, दिवालिया और विवादित उद्योगपति अनिल अंबानी और कुख्यात अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन के बीच हुए कुछ और कथित संवाद (चैट लीक) सामने आए हैं। इन दस्तावेज़ों में एक स्वीडिश लड़की की 'ऑफर' को लेकर प्रतिक्रिया और मुलाकात की योजना बनाने का संकेत दिए जाने का दावा किया गया है।

हालांकि, इस पूरे मामले पर अनिल अंबानी के प्रतिनिधियों ने किसी भी आधिकारिक टिप्पणी से इनकार किया है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी दस्तावेज़ों में यह भी दावा किया गया है कि एपस्टीन ने दुनिया भर के कई राजनेताओं को नाबालिग लड़कियाँ उपलब्ध कराईं। इन्हीं दस्तावेज़ों में भारत के अनिल अंबानी और जेफरी एपस्टीन के बीच कथित संवादों का उल्लेख होने से देश में हलचल मच गई

है। बताया जा रहा है कि २०१७ से २०१९ के बीच दोनों के बीच संदेशों के माध्यम से वैश्विक मुद्रों, व्यापार और महिलाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों ने निजी मुलाकातों की योजनाएँ भी बनाई थीं। दस्तावेज़ों के मुताबिक ९ मार्च २०१७ के एक कथित संदेश में अनिल



अभिनेत्री या मॉडल के बारे में पूछा, जिस

अंबानी ने एपस्टीन से पूछा-तुम किसकी सिफारिश करोगे? जवाब में एपस्टीन ने लंबी, गोरी स्वीडिश लड़की का उल्लेख किया, ताकि मुलाकात और मजेदार हो। दावा है कि २० सेकंड के भीतर अंबानी ने योजना बनाओ जैसा जवाब दिया। एक अन्य कथित संवाद में एपस्टीन ने अंबानी से उनकी पसंदीदा

पर अंबानी ने स्कारलेट जोहानसन का नाम लिया। उल्लेखनीय है कि उसी वर्ष रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित एक फ़िल्म में इस अभिनेत्री ने काम किया था। पेरिस और न्यूयॉर्क की मुलाकातों की चर्चा कथित संदेशों से यह भी सामने आया है कि दोनों ने पेरिस में मिलने पर चर्चा की, जो संभव नहीं हो सकी। इसके बाद जनवरी २०१८ में दावोंस में आयोजित विश्व आर्थिक

मंच के दौरान डोनाल्ड ट्रम्प की प्रतिक्रिया पर भी बातचीत होने का दावा किया गया है। मई २०१९ में अनिल अंबानी के न्यूयॉर्क जाने पर एपस्टीन ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया था। मैनहैटन स्थित एपस्टीन के निवास पर दोनों की मुलाकात होने की पुष्टि उनके सहायकों द्वारा किए जाने का दावा है। फिर भी, अनिल अंबानी के प्रतिनिधियों ने इस पर कोई आधिकारिक ▶▶पान ४ पे

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज से महाराष्ट्र सरकार का परहेज़-जनहित के खिलाफ फैसला

गरीब और मध्यम वर्ग में नाराज़गी, निर्णय रद्द करने की मांग

पुणे । मोहम्मद मुस्लिम कबीर महाराष्ट्र राज्य के सरकारी अस्पतालों में एक बार फिर इलाज के लिए शुल्क वसूलने का निर्णय लिया गया है। नए शुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला और महिला अस्पतालों तक लागू होंगे। बाढ्य रोगी विभाग (ओपीडी) की फीस ५ रुपये से शुरू होकर जॉइंट ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए ४०,००० रुपये तक निर्धारित की गई है।

उस समय के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने एक साहसिक निर्णय लेते हुए राज्य के सभी स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की शुरुआत की थी। यह निर्णय १५ अगस्त २०२३ से लागू हुआ था और तब से केस पेपर बनाने से लेकर रक्त जांच, अन्य सभी जांचें और उपचार पूरी तरह मुफ्त थे।

हालांकि, पिछले कुछ दिनों में स्वास्थ्य विभाग को यह महसूस हुआ कि यह व्यवस्था व्यावहारिक नहीं है। हाल ही में जारी सरकारी आदेश के अनुसार अब इलाज के लिए दोबारा शुल्क लागू कर दिया गया है।

इस फैसले पर विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि भले ही सरकारी आदेश में शुल्क कागज़ पर कम दिखाई देता हो, लेकिन सरकारी अस्पतालों में आने वाले अधिकांश मरीज समाज के सबसे कमजोर वर्ग से होते हैं, जिनके लिए मुफ्त इलाज अत्यंत आवश्यक है। कार्यकर्ताओं के अनुसार यह फैसला जनहित के विरुद्ध है। आदेश में सांसदों और

विधायकों के मुफ्त इलाज का उल्लेख है, जबकि वे वास्तव में सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं कराते। इसलिए सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।

नए शुल्क इस प्रकार हैं:

भर्ती मरीजों के लिए १० रुपये प्रतिदिन प्रवेश शुल्क

एमआरआई स्कैन: १,६०० रुपये

रक्त जांच (हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, ब्लड ग्रुप, आरएच), यूरीन केमिकल टेस्ट, कल्चर-सेंसिटिविटी: १५ रुपये प्रति जांच

किडनी और मूत्राशय जांच (इंट्रावीनस पायेलोग्राम एक्स-रे): १०० रुपये प्रति स्कैन

सिर का सीटी स्कैन: ३०० रुपये

रीढ़, गर्दन और छाती का

सीटी स्कैन: ४०० रुपये

एनेस्थीसिया के तहत छोटी-बड़ी सर्जरी: ६० से १६० रुपये

पहली डिलीवरी: मुफ्त

दूसरी डिलीवरी: ५० रुपये

इसके बाद की प्रत्येक डिलीवरी: २५० रुपये

एयरकंडीशंड कमरा: १५० रुपये प्रतिदिन

सामान्य कमरा: ७५ रुपये प्रतिदिन

आईसीयू: १०० रुपये

प्रत्येक डायलिसिस: १५० रुपये

शव को संरक्षित करने (एम्बाल्मिंग) की फीस: १,५०० रुपये

एंबुलेंस शुल्क: ५ रुपये प्रति किलोमीटर, ८ घंटे बाद ३० रुपये प्रति घंटा

जॉइंट ट्रांसप्लांट सर्जरी: ४०,००० रुपये

अन्य योजनाओं का लाभ जारी रहेगा

महाराष्ट्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार कुछ श्रेणियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा जारी रहेगी। इनमें सरकारी कर्मचारी और उनके परिजन, सरकारी अस्पतालों के मेडिकल अधिकारी व नर्स, व्यावसायिक व फिजियोथेरेपी के छात्र, न्यायिक हिरासत में व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिजन, मेडिकल-फॉरेंसिक मामलों के मरीज, न्यायिक जांच के तहत कैदी, पुलिस द्वारा रेफर किए गए मामले, कुछ रोग बोर्ड द्वारा रेफर मरीज, आश्रम स्कूलों व विधायक स्कूलों से रेफर मरीज, देवरूबन क्षेत्र के बच्चे तथा महिलाएं शामिल हैं।

के.एस.के. महाविद्यालय में वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साहपूर्वक संपन्न, छात्रों ने कला प्रतिभा का किया प्रभावी प्रदर्शन



बीड । प्रतिनिधि दि. ७

के.एस.के. महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने स्नेहसंमेलन के माध्यम से अपनी कला प्रतिभा का प्रभावी प्रदर्शन किया। स्नेहसंमेलन छात्रों को अपनी विविध छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच देने का एक उत्तम अवसर होता है, ऐसा प्रतिपादन नवगण शिक्षण संस्था के सचिव डॉ. योगेश क्षीरसागर ने किया।

बीड स्थित के.एस.के. महाविद्यालय में शुक्रवार को वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में डॉ. क्षीरसागर उपस्थित थे। मंच पर नगरसेवक गोविंद शिराळे, नंदकुमार पिंगळे, सामाजिक कार्यकर्ता अशोक शेजुळ, संस्था के सदस्य काजी आमेर सिद्दीकी एवं शुभम कांतागळे उपस्थित रहे।

विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए

गए लोकनृत्यों ने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। वर्षभर शैक्षणिक, क्रीड़ा एवं अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले मेधावी विद्यार्थियों का सत्कार कर उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

स्नेहसंमेलन के अंतर्गत आयोजित क्रीड़ा स्पर्धाएँ, नृत्य, संगीत एवं अन्य गतिविधियाँ शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न होने पर डॉ. क्षीरसागर ने संतोष व्यक्त किया।

महाविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनुरध गणगे, शिक्षकेतर कर्मचारी आर. टी. जाधव, कनिष्ठ महाविद्यालय के प्राध्यापक प्रा. अनिल जाधव, वरिष्ठ महाविद्यालय के डॉ. शंकर राऊत तथा महिला कर्मचारी डॉ. वंदना फटले को उत्कृष्ट कर्मचारी के रूप में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इसके साथ ही ग्रंथालय

विभाग के उत्कृष्ट पाठक विद्यार्थी, राष्ट्रीय सेवा योजना के आदर्श स्वयंसेवक तथा स्नेहसंमेलन के अवसर पर मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, सूक्ष्मजीवशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, जीवशास्त्र, भौतिकशास्त्र, गणित, गृहशास्त्र, भूगोल, एनसीसी, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नाट्यशास्त्र एवं क्रीड़ा विभागों के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर गौरवित किया गया।

कार्यक्रम में संस्था के प्रशासकीय अधिकारी डॉ. सुधाकर गुड्डे, डॉ. विश्वंभर देशमाने, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शिवानंद क्षीरसागर, उपप्राचार्य संजय पाटील देवळाणकर, उपप्राचार्य डॉ. अनिता शिंदे, स्नातकोत्तर विभाग प्रमुख डॉ. खान ए. एस., कनिष्ठ महाविद्यालय के उपप्राचार्य डॉ. नारायण काकडे, पर्यवेक्षक डॉ. जालिंदर कोळेकर सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे।

कार्यक्रम का सूत्रसंचालन डॉ. शंकर राऊत एवं प्रा. दत्तात्रय नेटके ने किया। इस अवसर पर शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी तथा विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

परीक्षा का सामना आत्मविश्वास के साथ करें, सफलता आपकी ही होगी: शेख अब्दुल रहीम

दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएँ विद्यार्थीदिशा ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन की दिशा तय करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षाएँ होती हैं। बारहवीं की परीक्षाएँ १० फरवरी से शुरू हो रही हैं, जबकि दसवीं की परीक्षाएँ २० फरवरी से आरंभ होंगी। शेष दिन परीक्षा-पूर्व तैयारी और वास्तविक परीक्षा अवधि के होते हैं, जो अत्यंत निर्णायक माने जाते हैं।

सालभर किए गए अध्ययन से भी अधिक, यही समय विद्यार्थियों को उज्ज्वल सफलता की ओर ले जाने में सहायक होता है। दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएँ भविष्य के निर्माण की नींव रखती हैं। इन परीक्षाओं में मिली सफलता से माता-पिता और पूरे परिवार को खुशी मिलती है, साथ ही विद्यार्थियों का समाज में सम्मान बढ़ता है। इतना ही नहीं, प्राप्त सफलता से आत्मसंतोष, मानसिक आनंद और आत्मविश्वास भी मिलता है। इसी कारण ये परीक्षाएँ बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

त्र परीक्षा के समय विद्यार्थियों के लिए १० महत्वपूर्ण सूत्र: संतुलित और पौष्टिक आहार लें। परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुँचें। तनाव न लें, स्वयं पर भरोसा रखें। पुस्तकों की बजाय अपनी बनाई हुई नोट्स पढ़ें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें।



परीक्षा से पहले स्वयं को प्रेरित करें। प्रवेश पत्र साथ रखना न भूलें। हाथ में घड़ी रखें और समय पर ध्यान दें। प्रश्नपत्र में दी गई सभी सूचनाएँ ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहले आसान स्तर के प्रश्न हल करें।

यदि अभिभावक घर में सकारात्मक और उत्साहपूर्ण वातावरण बनाए रखें, तो विद्यार्थियों का आधा तनाव वहीं कम हो जाता है। इस समय अंकों की तुलना करने के बजाय बच्चों के प्रयासों की सराहना करना अधिक आवश्यक है।

दसवीं और बारहवीं के सभी परीक्षार्थियों को उज्ज्वल सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ!

सफलता अंतिम नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती; अंततः साहस ही सबसे अधिक मायने रखता है।

देने का फैसला हुआ, जिसमें पहले सवा साल के लिए संजय घाड़ी को चुना गया।

ठाकरे गुट ने उम्मीदवार नहीं उतारा

भाजपा द्वारा उम्मीदवार दिए जाने के बाद उसके विरोध में अपना प्रत्याशी न उतारने का निर्णय ठाकरे गुट की बैठक में लिया गया। इस पर गुटनेता किशोरी पेडणेकर ने कहा, संख्याबल का गणित हमें पता है। हम केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे, लेकिन नई सदन में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे।

पक्षीय बलाबल

भाजपा: ८९

शिवसेना (ठाकरे गुट): ६५

शिवसेना (शिंदे गुट): २९

कांग्रेस: २४

एमआईएम: ८

मनसे: ६

राष्ट्रवादी (अजित पवार): ३

समाजवादी पार्टी: २

राष्ट्रवादी (शरद पवार): १

उल्लेखनीय है कि ऋतु तावड़े इससे पहले भी भाजपा की ओर से नगरसेविका रह चुकी हैं। वे पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ताओं में गिनी जाती हैं और २०१२ में वार्ड क्रमांक १२१ तथा २०२५ में



कर्तृत्व का शिवधनुष,डॉ.ज्योतिताई मेटे का संघर्षमय सफ़र

महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर लोकनेता की उपाधि को सार्थक करने वाला नेतृत्व स्वर्गीय विनायकराव मेटे साहब का रहा है। उनके आकस्मिक निधन से पूरा महाराष्ट्र स्तब्ध हो गया। लेकिन उनके बाद उनके विचारों की मशाल बुझने न देते हुए, जिस दृढ़ता से डॉ. ज्योतिताई मेटे ने यह शिवधनुष थामा है, वह उनके कर्तृत्व के प्रति सम्मान को दोगुना कर देता है। अरब सागर में शिवस्मारक हो या मराठा आरक्षण का लंबा संघर्ष-मेटे साहब ने हमेशा दो हाथ करने की भूमिका अपनाई।

ज्योतिताई ने स्वयं को केवल साहब की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि उनके विचारों की उत्तराधिकारी के रूप में सिद्ध किया है। साहब द्वारा खड़ा किया गया शिवसंग्राम और उन विचारों से बंधा कार्यकर्ता आज भी ज्योतिताई के रूप में साहब को खोजता है।

मेटे साहब के जाने से परिवार पर टूटा पहाड़ शब्दों में बयान करना कठिन था। फिर भी, ज्योतिताई ने अपने व्यक्तिगत दुःख को किनारे रखकर मातृत्व और कर्तव्य का सुंदर संतुलन साधा। बच्चों के सिर से छाया उठ जाने पर उन्हें सहारा देना और साथ ही साहब के शिवसंग्राम परिवार को अनाथ न होने देना-इन दोनों मोर्चों पर वे अकेले संघर्ष कर रही हैं।

इस सफ़र में उनकी दमछाक केवल शारीरिक थकान नहीं, बल्कि मानसिक संघर्ष भी है-जहाँ साहब की अनुपस्थिति में हर महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय उन्हें अपने ही मन से लड़ना पड़ता है। साहब ने जो सपने देखे थे, उन्हें पूरा करने के लिए वे



अतुल लांगोरे

शब्दांकन

हैं। घर की देहरी और समाज की ज़िम्मेदारी-दोनों मोर्चों पर लड़ते हुए वे अपने अस्तित्व का त्याग कर लक्ष्य के लिए जुटी हैं।

लोकनेता स्व. विनायकराव मेटे के निधन से केवल एक परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे मराठा समाज को अपूरणीय क्षति पहुँची है। उनके बाद डॉ. ज्योतिताई मेटे ने शासकीय सेवा का त्याग कर मज़बूती से नेतृत्व संभाला-ऐसे समय में उनका

राजनीतिक पुनर्वसन अपेक्षित था। पर राजनीति के इस कठोर मैदान में एक जिद्दी नेतृत्व की उपेक्षा की गई, जो खेदजनक है।

राजनीति में विरासत संभालने की परंपरा नई नहीं-कई नेताओं के बाद उनके परिजनों को राजनीतिक सहारा मिला। लेकिन दुर्भाग्य से मेटे साहब के मामले में यह न्याय बदला हुआ दिखा। मराठा आरक्षण के लिए साहब ने जीवन समर्पित किया, पर उनकी विरासत को संभालने में राजनीतिक दलों ने सुविधाजनक मौन साध लिया। एक ओर साहब के नाम का जयघोष और दूसरी ओर उनके विचारों की धुरा उठाने वाली ज्योतिताई के हाथ को ताक़त देने से कतराना-यह दोहरापन समाज की नज़र से छुपा नहीं है।

डॉ. ज्योतिताई मेटे की स्थिति केवल किसी व्यक्ति की उपेक्षा नहीं, बल्कि संघर्ष की विरासत आगे बढ़ाने वाले एक निष्ठावान नेतृत्व के साथ अन्याय है-जिसका उत्तर समय आने पर मिलेगा।

मेटे साहब के बाद राजनीतिक परिदृश्य में कई उतार-चढ़ाव आए, पर ज्योतिताई डगमगाई नहीं। चेहरे पर थकान छुपाकर, मज़बूती से खड़ी ज्योतिताई में छिपी शक्ति और त्याग स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने केवल साहब का नाम आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उनके कार्य को नई दिशा देने का प्रयास किया है।

लोकनेता विनायकराव मेटे ने समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया; आज उनके बाद ज्योतिताई वही विरासत आगे बढ़ाने के लिए अथक परिश्रम कर रही हैं। ऐसे में समाज के रूप में उनके साथ मज़बूती से खड़ा होना-यही साहब को सच्ची श्रद्धांजलि और ज्योतिताई के प्रति सच्ची कृतज्ञता

होगी।

ज्योतिताई का यह सफ़र केवल एक महिला का संघर्ष नहीं, बल्कि लक्ष्यनिष्ठ प्रेरणा का सफ़र है। उन्होंने जो शिवधनुष उठाया है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी बनेगा। साहब के विचारों की विरासत और ज्योतिताई के कर्तृत्व के संगम से समाजहित का कार्य अविराम चलता रहेगा-इसमें कोई संदेह नहीं।

वार्ड क्रमांक १३२ से निर्वाचित हुई हैं।

अनिल अंबानी और कुख्यात जेफरी...

प्रतिक्रिया नहीं दी है।

बताया जा रहा है कि २०१७ में एफस्टीन द्वारा मॅंगाई गई कुछ डिजिटल पुस्तकों-लरपळ डेपी और डोंगी छप हॅश इशर थळपच-के माध्यम से उसे अंबानी परिवार के इतिहास और सामाजिक हैसियत की जानकारी मिली होगी।

धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश और अनिल अंबानी के बीच कारोबार का विभाजन हुआ था। वर्तमान में अनिल अंबानी रिलायंस समूह के अध्यक्ष हैं, जबकि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नेतृत्व कर रहे हैं और एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में अनिल अंबानी की आर्थिक स्थिति में भारी गिरावट आई है। २०१९ में मुकेश अंबानी द्वारा ८० मिलियन डॉलर का कर्ज़ चुकाए जाने से अनिल अंबानी को जेल जाने से बचाया गया था। वर्तमान में विभिन्न जाँच एजेंसियाँ उनके मामलों की पड़ताल कर रही हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जाँच एजेंसियों को अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों से जुड़े कथित ४०० अरब रुपये (लगभग ४.४ अरब डॉलर) के बैंक ऋण घोटाले की जाँच तेज़ करने के निर्देश दिए हैं।